

# 'अमेरिका, उन देशों पर जो रूस से ऑयल खरीदना जारी रखेंगे, 500 प्रतिशत टैरिफ लगायेगा'

**अमेरिका के सिनेट में प्रस्तुत इस विधेयक, जिसे दोनों पार्टियों, रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक पार्टी, का आंशिक समर्थन प्राप्त है, का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा**

-सुकमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-  
वार्षिकान्टर/एड दिल्ली, 3 जुलाई। अमेरिकी सिनेट में पेश एक नया बिल (वैनियरिंग रिशियर एक्ट ऑफ 2025, एस.1241) यह तात्पुर है कि जो ऑयल, जिनमें भारत भी शामिल है, से रूस से तेल, गैस, पैट्रोकेमिकल और यूरोपीय की खरीदारी रखेंगे, उनके उत्पादों पर अमेरिका 500 प्रतिशत टैरिफ (आरोपात्ति) लगा सकता है।

यह विधेयक सोनोटर लिंडेसे ग्राहम और चिर्च ब्लूरो द्वारा देखा गया है और इसे 80 से अधिक सीमें दोनों का समर्थन प्राप्त है। डॉनल्ड ट्रम्प ने न केवल इस विधेयक के कारणमें पारित होने का समर्थन किया है, बल्कि भविष्य के राष्ट्रपतियों को रखने पर दबाव बनाने के लिए एक "टूलबाब्स" देने की वाकात की है, हालांकि उन्होंने इसमें एक प्रैज़िडेंशियल छूट का प्रावधान भी सुनिश्चित किया है, जिससे राष्ट्रपति चाहे तो टैरिफ को निर्लिपित कर सकते हैं।

- रूस ने प्रत्युत्तर में घोटाया है कि भारत जैसे देश पर इस तरह का दबाव बनाना, यूक्रेन में चल रहे शांति प्रयासों को जोखिम में डाल सकता है।
- भारत, अमेरिका का फार्मास्यूटिकल्स, ईक्सटाइल्स, आईटी सर्विसज, ऑटो पार्ट्स तथा जावाहरात निर्यात करता है। भारत के ये निर्यात, अमेरिका में बिना किसी रुकावट के पहुंचते हैं। पर, अगर, अमेरिका ने भारत के इस निर्यात पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाया तो ये आइटम इतने महंगे हो जायेंगे कि अमेरिका में इनकी बढ़िया खत्म सी हो जायेगी।
- अमेरिका अपनी इकोनॉमिक ताकत का उपयोग, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए काम ले सकता है। अतः भारत ने अब ज्यादा से ज्यादा ऑयल अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे वो अमेरिका की व्यवसायिक धमकी में भी जी सके तथा अमेरिका के समृद्ध मार्केट में दीर्घकालीन एन्ट्री बनाये रख सके।

क्रेमलिन ने घेताकरी दी है कि भारत जैसे प्रमुख खरीदारों पर दबाव

डालने जैसे कदम युक्त हैं कि भारत जैसे देश पर इस तरह का दबाव बनाना, यूक्रेन में शांति प्रयासों को जोखिम में डाल सकता है।

विशेषज्ञों का मानाना है कि यह 500 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव एक गंभीर खत्ता है। यह उन देशों को निशाना बनाता है, जो रूस से तेल खरीद जारी रखते हैं, लेकिन यह दंड सीधे उनके तेल व्यापार पर लागू नहीं होता।

भारत के संदर्भ में, यद्यपि वह अपनी कुल जस्तर के कच्चे तेल 40 प्रतिशत आयत रूस से करता है, लेकिन अमेरिका को वह तेल निर्यात नहीं करता, तर्ज श्वेत में प्रत्यक्ष टैरिफ लगाने को ईड रूस प्रत्यक्ष नहीं है।

भारत को वह झटका किसी और क्षेत्र से लग सकता है, खासकर अन्य क्षेत्रों में अमेरिका को किये जाने वाले निर्यात से।

इन क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, बस्ट, आईटी सेवाएं, ऑटो पार्ट्स और रस्ल-आधुनिक शामिल हैं, जो फिलहाल अमेरिका में न्यूतम व्यापार बाधाओं के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी को मिला घाना का सर्वोच्च सम्मान

अबकारा/नवी दिल्ली, 03 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घाना के सर्वोच्च सम्मान, 'द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें यसमान प्रदान किया। मोदी ने बुधवार को इस सम्मान के लिए घाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे 'अलंकृत गर्व का विषय' बताया। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों को और से पुरस्कार स्वीकार करते हुए इस सम्मान के युवाओं की आकांक्षाओं, इसकी सांस्कृतिक परंपराओं और विविधता तथा घाना और

## बिहार में मतदाता के धार्मिक ध्वनीकरण की राजनीति शुरू हो गई?

**भाजपा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर "नमाजवादी" होने का व्यंग्य दागा तथा विपक्ष ने भाजपा पर एनआरसी (नैशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन्स) को पीछे के दरवाजे से लाकर लागू करने का आरोप लगाया**

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 3, जुलाई। चुनाव की ओर बढ़ रहे बिहार में मतदाताओं का धार्मिक आयात पर ध्वनीकरण शुरू हो गया है। जहाँ भाजपा ने राजदूत (राष्ट्रपति जॉन दल) नेता तेजस्वी यादव पर "नमाजवादी" तंज करते हुए इसकी शुरुआत की, वहाँ विपक्षी नेताओं ने एनडीए पर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया है।

तेजस्वी यादव द्वारा यह कहे जाने पर किंवदं एक एक्ट को कर्क चर्चे में फैक्ट दिया जाएगा और बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। खासकर एनआरसी को विपक्षी नेताओं ने एनडीए पर महागठबंधन के नेताओं पर शरियां करने लागू करने की मांसपात्री रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह विवाद है कि घाना की उक्ती ऐतिहासिक राजकीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ तेजस्वी यादव का दावा है कि वक्फ एक्ट को कुड़ी की टोकरी में फैक्ट दिया जायेगा तथा बिहार में कभी लागू नहीं होगा, पर, संवित पात्रा ने कहा कि महागठबंधन बिहार में "शरिया कानून" लागू करना चाहता है।

■ प.बंगल की मु.मंत्री ने कहा कि बिहार में स्पैशल इन्वैन्सिव रिवीज़न (एसआईआर) को लागू करने का असली टारगेट तो प.बंगल है। बंगल के ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं के नाम मिटा दिए जाएंगे तथा उनकी जगह, बिहार, यू.पी., राजस्थान, हरियाणा आदि के मतदाताओं से भर दी जायेगी।

■ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मु.मंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में बिहार में बारे-में कहा था, "कहाँ का एनआरसी। बिल्कुल लागू नहीं होगा।" देखना है, अब उनका रुख क्या रहता है।

इस बीच, चुनाव आयोग द्वारा निर्णय को लेकर एक बड़ा विवाद बिहार की मतदाता सूचीयों के विषय उभरता दिख रहा है। इस प्रक्रिया के गहन पुनरीक्षण के दौरान नेताओं से भरी तरफ तेजस्वी यादव के निर्वाचन सदन ने निर्णय लिया कि केवल पार्टी द्वारा मनोनीत एक नेता ही चुनाव आयुर्त से मिल सकेगा।

## 'एस.आई.आर. लागू हुआ तो बिहार के 20% मतदाता अपना "वोटिंग" का अधिकार खो देंगे'

**इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार के "माइग्रेंट वर्कर" (घुमंतु मजदूर) 1 महीने में अपने आप को नये तरीके से मतदाता के रूप में "रजिस्टर" नहीं कर पायेंगे**

-श्रीनंद झा -

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 3, जुलाई। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग द्वारा राज्य की मतदाता सूची को सेसेल इन्वैन्सिव विक्र (एस.आई.आर.) का नेता कर्ता वैकल्पिक रूप से फैसला द्वारा तक राजदूत के कारण दिया गया है।

बुधवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ विषयी गठबंधन के बैठक में, इन्होंने कहा कि यह विक्रियात्व का विकास नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विक्रियात्व का विकास नहीं है।

बुधवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ विषयी गठबंधन के बैठक में, इन्होंने कहा कि यह विक्रियात्व का विकास नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह विक्रियात्व का विकास नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विक्रियात्व का विकास नहीं है।

किंवदं विभिन्न दलों के 20 सदस्यों का सिंह बैठक में शामिल नहीं हो सके और प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन सदन पूर्ण हुआ।

उन्हें लगाने वाले चंदे तक बाहर इंटर्न आई और अलोकांशक्रिया कर्मदाता ने एक विकास नेता के रूप में प्रदेशाध्यक्ष अधिलेख प्रसाद सिंह, चुनाव आयोग के साथ मीटिंग में भाग नहीं ले पाये और तीन घंटे बाहर रहे।

क्योंकि, अचानक निर्वाचन सदन ने निर्णय लिया कि केवल पार्टी द्वारा मनोनीत एक नेता ही चुनाव आयुर्त से मिल सकेगा।

सिंह बैठक में शामिल नहीं हो सके और प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन सदन पूर्ण हुआ।

उन्हें लगाने वाले चंदे तक बाहर इंटर्न आई और अलोकांशक्रिया कर्मदाता ने एक विक्रियात्व का विकास नहीं है।

## विचार बिन्दु

मूर्ति के समान मनुष्य का जीवन सभी ओर से सुन्दर होना चाहिए। -सुकरात

**ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।  
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥**

-ईशावास्योपनिषद

सं

विधान की उद्देशिका में 'समाजबाद' व 'धर्म निरपेक्ष' शब्दों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 से जोड़ा गया है। यह संघोंने 03.01.1977 को लागू होता है। यह संघ यथा था कि बाद देख में आपातकाल लागू होता है। देश के नायिकों के मूल अधिकार लंबित किये गये थे और एक सीमा तक न्यायालयों की न्यायिक अधिकारों को भी सीमित कर दिये गये थे। इन दो शब्दों के अधिकार एक अन्य शब्द एकता (Unity) को भी जोड़ा गया था; किन्तु विवाद उन्हें दो शब्दों के बाबत ही होता है।

उन दो शब्दों को लेकर राजनीति में बंबिडर उठ खड़ा हुआ था। कई वर्षों के बाद अब पुनः बंबिडर ने जो पंडा है।

इस बंबिडर की अग्रिम में घी डालने का काम संघ के सरकारीवाह दत्तत्रेय होसबले ने किया है, जिसने पुरजों शब्दों में उत्तर दोनों शब्दों को संविधान से हटाये जाने को रोकी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दत्तत्रेय होसबले का समर्थन किया है। दोनों का माना है कि 42वां संविधान संघोंने आपातकाल की देने हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए। इन्हें, शिवराज सिंह ने यह भी कहा है कि इनको हटाये जाने के बाबत विचार होना चाहिये। देश के उपराष्ट्रीय न्यायिक धनविष्ठ की उत्तरी शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की उत्तरी शब्द रख दिये गए थे। इन दो शब्दों के अधिकार एक अन्य शब्द एकता (Unity) को भी जोड़ा गया था; किन्तु विवाद उन्हें दो शब्दों के बाबत ही होता है।

देश की राजनीति का पार्टीमें में जो आमने कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है। यह देश में संविधान निरामातों की मंसा के साथ शामों में पहले ही से अन्यान्य थोकबाटी के केस में आमनीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायुति रामाधारों के माध्यम से कहा था, वह समीक्षा है। उहोंने कहा है।

"उद्देशिका संविधान का अधिन अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघातक दंवा, राष्ट्र की पंडिता और अखण्डा, धर्मनिरपेक्ष, समाजबाद, समाजिक न्याय तथा न्यायिक पुरुषालाला संविधान के बुनियादी तरीकों में स्थान देने की है।"

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में माना कि "हमारे संविधान को विस्तृत बुनियादी तरीकों पर निर्मित है, यह उत्तर देखिकों को लागू होता है। यह संविधान का दौड़ा ही दृढ़ा जावा और संविधान वही नहीं रहेगा तथा अपनी पहचान ही हो देता है।" इसका अर्थ यह है कि संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं हो सकता बेलारी व इन्दिरा गांधी बनाम राज न्यायालय के केस में भी न्यायालय का यही विचार देखा जा सकता है। बेलारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है, शब्दकृत है, अपरिवर्तनीय है।" उद्देशिका के बाबत कुछ न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

संविधान निर्माता सभा की कार्यालयीं पर यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कानून निर्माताओं के अनुसार समाजबाद, धर्मनिरपेक्ष (पार्थ निरपेक्ष) और राष्ट्र एकता उद्देशिका में तथा मूलरूप से निर्मित संविधान के शेष भागों में पहले ही से अन्यान्य थोकबाटी के केस में आमनीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से कहा था, वह समीक्षा है। उहोंने कहा है।

"उद्देशिका संविधान का अधिन अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघातक दंवा, राष्ट्र की पंडिता और अखण्डा, धर्मनिरपेक्ष, समाजबाद, समाजिक न्याय तथा न्यायिक पुरुषालाला संविधान के बुनियादी तरीकों में स्थान देने की है।" उद्देशिका को लागू होने के बाबत विचार होता है। यह संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं हो सकता बेलारी व इन्दिरा गांधी बनाम राज न्यायालय के केस में भी न्यायालय का यही विचार देखा जा सकता है। बेलारी के केस में यशस्वी न्यायालय द्वारा कटुता आई है, उद्देशिका के बाबत कुछ न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

संविधान निर्माता की कार्यालयीं पर यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कानून निर्माताओं के अनुसार समाजबाद, धर्मनिरपेक्ष (पार्थ निरपेक्ष) और राष्ट्र एकता उद्देशिका में तथा मूलरूप से निर्मित संविधान के शेष भागों में पहले ही से अन्यान्य थोकबाटी के केस में आमनीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से कहा था, वह समीक्षा है। उहोंने कहा है।

इन दोनों शब्दों को यदि हम अब हटा भी दें तो भी हमारा संविधान का आंतरिकीय और धर्मनिरपेक्ष राज्य ही माना जावेगा। पहले वाला संशोधन असंवैधानिक था तो क्या

हम पुनः उन दो शब्दों को निकाल कर असंवैधानिक संशोधन करें? पूर्व संशोधन अवैध था अर्थात् शून्य था। हमारा संविधान

पूर्ण है। पूर्ण से कुछ भी निकला जावे या

घटाया जावे फिर भी पूर्ण ही रहता है। यह ईशोपानिषद का शान्ति भ्रंत है।

ये ने समाजबाद को पश्चिमी समाजबाद और धर्म निरपेक्षबाद को विदेशी विचारधारा माना है। वर्तमान समाजबादी पार्टी ऐसे समाजबाद को तुकोरीकरण बादी मानती है।

दत्तत्रेय हीसबले व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की उत्तर दो शब्दों के उद्देशिका में जोड़े जाने के बाबत विचार दर्शकों के बाबत हो रहा है। इस पर यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है, शब्दकृत है, अपरिवर्तनीय है।" उद्देशिका के बाबत कुछ न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

गोलबलवर क जो संघ के दूरूरे सर्वसंघालक के बाबत विचारधारा या बाद के बाबत विचार दर्शकों के बाबत हो रहा है। यह संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

यह निगह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देशिका संविधान का आंतरिकीय केशवाननद भारतीय के केस में अधिकांश न्यायालयों में जो आमनीय कटुता आई है, उसे देखें हुये कडवाहट क कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरनी है।

यह निगह डालें











